



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—४, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 28 नवम्बर, 2024

अग्रहायण 7, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त विभाग

संख्या बी—४—७७९ / X-२०२४-१०(२८) -९४

लखनऊ, 28 नवम्बर, 2024

अधिसूचना

प०आ०—३१३

उत्तर प्रदेश सरकार की प्रत्याभूति मोचन निधि के गठन एवं प्रशासन के लिए योजना

उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या बी—४—४६—२०२१/X—१०(२८)-९४, दिनांक 29 जनवरी, 2021 और संख्या 418 / 2022 / B—४ / X—१०(२८)-९४, दिनांक 31 दिसंबर, 2022 का अधिक्रमण करके उत्तर प्रदेश सरकार, एतद्वारा मोचन निधि की स्थापना के लिए योजना को निम्नानुसार अधिसूचित करती है :

1—यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की 'प्रत्याभूति मोचन निधि' (जिसे आगे 'निधि' कहा गया है) योजना कहलायेगी।

2—उत्तर प्रदेश सरकार (जिसे आगे 'सरकार' कहा गया है) द्वारा राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों की ओर से निर्गत प्रत्याभूति से उद्भूत होने वाले अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए एक 'प्रत्याभूति मोचन निधि' सृजित की जायेगी।

निधि का सृजन सरकार के लोक लेखा में किया जाएगा तथा इसका वर्गीकरण लेखाशीर्ष "8235— सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ—117— प्रत्याभूति मोचन निधि—01— प्रत्याभूति मोचन निधि" में किया जाएगा।

3—इस निधि का उपयोग राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा निर्गत बंध-पत्रों एवं अन्य ऋणों के संबंध में सरकार द्वारा निर्गत प्रत्याभूतियां जो हितधारकों द्वारा निवेदित की गयी हों, से उद्भूत होने वाली भुगतान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :-

(क) निधि में संचित धनराशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा निर्गत की गई तथा लाभार्थी द्वारा निवेदित की गयी प्रत्याभूतियों के भुगतान के लिए किया जायेगा और उस संस्था द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा जिसकी ओर से प्रत्याभूति निर्गत की गयी थी।

(ख) राज्य, अस्थायी नकदी प्रवाह विसंगतियों को पूरा करने के लिए, निधि में किए गए निवेश के संपार्शिक के विरुद्ध, भारतीय रिजर्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) से विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के तहत अन्यकालिक सुविधा का लाभ उठा सकता है, जो समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा।

योजना के क्रियान्वयन का प्रारंभ

निधि में अभिदान

4—योजना अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी।

5—(क) सरकार को निधि के गठन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर अदत्त प्रत्याभूतियों के पांच प्रतिशत तक के निधि कोष का निर्माण करने की दिशा में सचेष्ट प्रयास करना चाहिए।

(ख) सरकार स्व-विवेकानुसार तथा संभावित निवेदित की जाने वाली प्रत्याभूतियों के अपने आंकलन के आधार पर निधि में अभिदान बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। निधि में शेष राशि को वार्षिक या लघु अंतराल पर आवधिक अभिदान के साथ बढ़ाया जाएगा।

(ग) निधि में अभिदान की कुल धनराशि के हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए, सरकार द्वारा बजट के राजस्व व्यय पक्ष के अंतर्गत लेखाशीर्ष " 2075— विविध सामान्य सेवाएं—797—आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण —03— प्रत्याभूति मोचन निधि" के अंतर्गत उपयुक्त बजट का प्रावधान किया जायेगा।

(घ) सरकार द्वारा निधि में अपने अभिदान का वित्तपोषण बैंक से लिये गये ऋण से नहीं किया जायेगा।

सामान्य राजस्व/लोक लेखा खाते के साथ निधि का संबंध

6—(क) निधि के कोष में, सरकार द्वारा निर्धारित कोई आरंभिक राशि, सरकार द्वारा किया गया वार्षिक या अन्य अभिदान निधि में प्राप्त होने वाली आय के अतिरिक्त, उन संस्थाओं से एकत्रित प्रत्याभूति कमीशन के रूप में आवधिक वृद्धि भी सम्मिलित होती है, जिनके बन्ध—पत्रों/दायित्वों के सम्बन्ध में सरकार प्रत्याभूति निर्गत करेगी।

(ख) निधि को सरकार के सामान्य राजस्व से पृथक रखा जायेगा तथा इसका उपयोग केवल इस योजना में विहित रीति से किया जाएगा।

निधि का प्रशासन

कोष की निधि का निवेश

7—निधि का प्रशासन बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग द्वारा किया जाएगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किए जाने वाले दिशा—निर्देशों/अनुदेशों के अधीन होगा।

8—निधि में वृद्धि के साथ—साथ निधि के निवेश पर अर्जित आय को भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, राजकोषीय बिलों, भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों तथा अन्य राज्यों की राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में ऐसी परिपक्वता अवधि के रूप में निवेश किया जायेगा, जैसा कि बैंक समय-समय पर निर्धारित करेगा। बैंक अपनी निवेश संग्रह से या द्वितीयक बाजार से प्रतिभूतियों प्राप्त करके, प्रस्तर—11 में निर्दिष्ट अधिभार के अतिरिक्त कोई अन्य अधिभार लगाये बिना, निवेश के लिए प्रतिभूतियों उपलब्ध कराएगा।

संव्यवहारों का लेखांकन

9—(क) निधि के प्रशासन का उत्तरदायित्व सरकार का होगा। सरकार कोष की निधि के निवेश, पुनर्निवेश/विनिवेश, निधि के दायित्वों और उपयोग आदि से संबंधित सभी प्रकरणों पर निर्णय लेगी।

(ख) सरकार समय-समय पर बैंक को निर्देश निर्गत करेगी। बैंक तत्काल आवश्यक निवेश करने की व्यवस्था करेगा। बैंक, निवेश तथा अन्य आनुषांगिक प्रभारों यथा ब्रोकरेज, कमीशन आदि से सम्बन्धित डेबिट का मसौदा सामान्य तरीके से सरकार को प्रेषित करेगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि के निवेश से सम्बन्धित संव्यवहार अन्य संव्यवहारों के साथ मिश्रित न हों, इन्हें पृथक—पृथक मसौदों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जा सकता है।

(ग) मसौदे प्राप्त होने पर निवेश सम्बन्धी संव्यवहारों का लेखांकन "8235— सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ—120— प्रत्याभूति मोचन निधि—निवेश खाता" लेखाशीर्ष के अंतर्गत किया जाएगा। यद्यपि, ब्रोकरेज, कमीशन आदि जैसे आनुषांगिक शुल्कों को निधि पर प्रभार के रूप में लिया जाएगा।

(घ) बैंक इन प्रतिभूतियों पर ब्याज संग्रहित करने तथा नियत तिथि पर उसे निधि में जमा करने की व्यवस्था करेगा। इसके अतिरिक्त इनको सरकार के अभिदान की भाँति, निवेशित किया जाना आवश्यक होगा, अर्थात्, उपर्युक्त प्रस्तर-8 में विहित निवेश सम्बन्धी मानदंडों के अनुसार।

(ङ) प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर, आगमों को संग्रहित किया जाएगा और सरकार के खाते में जमा किया जाएगा या सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के आधार पर उपर्युक्त प्रस्तर-8 में रेखांकित व्यवस्था के अनुसार पुनर्निवेश किया जाएगा। डेबिट मसौदे की भाँति, प्राप्तियों के लिए बैंक द्वारा पृथक मसौदे का उपयोग किया जायेगा।

(च) सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर, बैंक प्रतिभूतियों का विक्रय प्रचलित मूल्य पर करने की व्यवस्था करेगा और प्राप्त राशि को, आनुषांगिक प्रभारों को घटाकर, सरकार के खाते में जमा करेगा। यदि ये प्रतिभूतियाँ घाटे में हैं, तो बैंक सरकार के परामर्श से प्रतिभूतियों को परिसमाप्त करने का निर्णय ले सकता है।

(छ) प्रतिभूतियों की परिपक्वता अथवा विक्रय से होने वाली प्राप्तियों को " प्रत्याभूति मोचन—निधि निवेश खाते" के खाते में जमा किया जाएगा। विक्रय में होने वाले आनुषांगिक प्रभारों को निधि पर भारित किया जायेगा।

(ज) प्रत्याभूति मोचन के कारण होने वाले व्यय का प्रावधान सरकार के आय—व्ययक में सुसंगत लेखाशीर्ष के अधीन किया जायेगा। प्रत्याभूति मोचन हेतु व्यय की केवल वास्तविक धनराशि ही लेखाशीर्ष "8235—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ—120—प्रत्याभूति मोचन निधि—निवेश—खाता" के अधीन लेखांकित की जायेगी।

(झ) बैंक परिपक्वता पर प्रतिभूतियों के मोचन करने की व्यवस्था करेगा। समय से पूर्व विनिवेश की दशा में, दावों के भुगतान के दायित्व को पूरा करने के लिए बैंक परिसमाप्त की जाने वाली प्रतिभूतियों पर निर्णय लेगा और प्रतिभूतियों को प्रचलित मूल्य पर बेचेगा तथा प्राप्त राशि को, आनुषांगिक प्रभारों को घटाकर, सरकारी खाते में जमा करेगा। यदि ये प्रतिभूतियाँ घाटे में हैं, तो बैंक सरकार के परामर्श से प्रतिभूतियों को परिसमाप्त करने का निर्णय ले सकता है।

(ण) सरकार के परामर्श से बैंक द्वारा निर्धारित दर पर, सरकार बैंक को कमीशन का भुगतान करेगी। यह अधिभार भी प्रस्तर 9 (ग) और 9 (छ) में दर्शाए गए शुल्कों की भाँति निधि द्वारा वहन किए जाएंगे। प्रतिभूतियों के विक्रय से होने वाली हानि या लाभ को भी निधि के खाते में लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण:—

(क) ऐसे प्रत्याहरण के फलस्वरूप सरकार को डेबिट का लेखांकन मुख्य लेखाशीर्ष "8235— सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ—120— प्रत्याभूति मोचन निधि—निवेश खाता" के अंतर्गत किया जाएगा। ऋण की परिपक्वता पर लेखाशीर्ष "8235— सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ—117— प्रत्याभूति मोचन निधि" के अंतर्गत अवशेष राशि को लेखाशीर्ष "8680— विविध सरकारी लेखे—101—खाता शेष समायोजन लेखा" में जमा किया जाता है।

(ख) बैंक सरकार को निवेश के कारण होने वाले ऋण में से सामान्यतः प्रयोज्य होने वाले आक्रिमक अधिभारों को घटाकर राशि देगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि के निवेश से सम्बन्धित संव्यवहार अन्य संव्यवहारों के साथ मिश्रित न हों, इन्हें पृथक—पृथक मसौदों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा।

(ग) बैंक निवेश पर नियत तिथियों पर ब्याज संग्रहित करने तथा उसे निधि में जमा करने की व्यवस्था करेगा।

(घ) बैंक, प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर, प्रतिभूतियों का मोचन कराये जाने की व्यवस्था करेगा और समय से पूर्व विनिवेश के प्रकरण में, प्रतिभूतियों का विक्रय प्रचलित मूल्य

पर करेगा तथा प्राप्त राशि से अनुषांगिक अधिभारों को घटाते हुए प्रत्याभूति मोचन निधि निवेश खाते में जमा करेगा। डेबिट मसौदों के प्रकरण में, बैंक प्राप्तियों के लिए पृथक मसौदों का प्रयोग करेगा।

(ङ) आवधिक अभिदान पर व्यय के लिए सरकार के आय व्ययक से संबंधित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान किया जाएगा। निधि से वित्तपोषित किए जाने वाले व्यय की सीमा तक धनराशि का निधि से प्रत्याहरण निवेश के निपटान द्वारा किया जायेगा।

निधि का प्रबंधन
करने वाले बैंक के
कार्य

10-(क) निधि से समय समय पर निवेश/पुनर्निवेश/विनिवेश/पुनर्अवंटन/प्रत्याहरण से संबंधित सभी प्रकरणों में बैंक सरकार के दिशा-निर्देशों द्वारा निर्देशित होगा तथा तदनुसार कार्य करेगा।

(ख) बैंक प्रस्तर-5 में उल्लिखित अभिदानों की सूची के अनुसार अपने पास रक्षित सरकार के खाते को डेबिट बढ़ाने की व्यवस्था करेगा।

(ग) निधि में किये गये अभिदानों का निवेश बैंक द्वारा प्रस्तर-8 में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार किया जाएगा। प्रत्याभूति शुल्क, सरकार द्वारा किये गये अभिदानों और व्याज से होने वाली आय के माध्यम से निधि में आवधिक वृद्धि को भी बैंक द्वारा इसी रीति में निवेशित किया जायेगा।

(घ) विगत वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को निधि में बकाया कोष का 50 प्रतिशत अथवा उस वर्ष (अप्रैल–मार्च) के दौरान निवेदित की गई प्रत्याभूतियों की राशि, जो भी कम हो, को वर्ष के दौरान निधि से प्रत्याहरण के लिए अधिकतम पात्र सीमा तक पहुंचने के लिए आगणित किया जाना चाहिए। सरकार अगला प्रत्याहरण करने से पूर्व कोष की पुनः पूर्ति करेगी।

(ङ) बैंक सरकार के परामर्श से अवशेष राशि का आवधिक विवरण/उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में सलाह प्रस्तुत करेगा।

निधि के प्रशासन
हेतु सेवा अधिभार

11—सरकार बैंक को, निधि के टर्नओवर के एक प्रतिशत के 1/8 प्रतिशत की दर से अथवा समय—समय पर पारस्परिक सहमति से निर्धारित की जाने वाली दर पर कमीशन का भुगतान करेगी।

लेखा और संपरीक्षा

12—निधि और निवेशों के लेखे को सामान्य रूप से राज्य के महालेखाकार द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा। सरकार का संबंधित विभाग सहायक लेखाओं को ऐसी रीति और विवरणों से अनुरक्षित करेगा जैसा कि सरकार द्वारा महालेखाकार के परामर्श से विचारण करके निर्धारित किया जायेगा।

व्यावृति

13—सरकार योजना के सुचारू संचालन को सक्षम करने के लिए समय—समय पर विचारण करके योजना के प्रावधानों से संबंधित दिशा-निर्देश निर्गत करेगी। योजना के किसी प्रावधान के संचालन में किसी भी कठिनाई की दशा में, सरकार यदि संतुष्ट हो तो ऐसे प्रावधानों को शिथिल कर सकती है।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव ।

No. B-4-779/X-2024-10(28)-94

Dated Lucknow, November 28, 2024

**SCHEME FOR CONSTITUTION AND ADMINISTRATION OF THE
GUARANTEE REDEMPTION FUND OF THE GOVERNMENT OF
UTTAR PRADESH**

IN suppression of the government letter no. B-4-46-2021/X-10(28)-94 dated January 29, 2021 and no. 418/2022/B-4/X-10(28)/94 dated December 31, 2022, the Government of Uttar Pradesh, hereby, notifies the scheme for setting up of the Guarantee Redemption fund of Government of Uttar Pradesh as follows:-

<p>1. The Scheme shall be called 'Guarantee Redemption Fund' (hereinafter referred to as 'the Fund') Scheme of the Government of Uttar Pradesh.</p> <p>2. A 'Guarantee Redemption Fund' shall be constituted by the Government of Uttar Pradesh (hereinafter called the Government) for meeting its obligations arising out of the Guarantees issued on behalf of State Level Public Sector Undertakings or Other Bodies.</p> <p>The Fund shall be constituted in the Public Account and classified under the head "8235- General and Other Reserve Funds-117-Guarantee Redemption Fund-01-Guarantee Redemption Fund" in the accounts of the Government.</p> <p>3. The Fund shall be utilised for meeting the payment obligations arising out of the guarantees issued by the Government in respect of bonds issued and other borrowings by the State Level Public Sector Undertakings or Other Bodies and invoked by the beneficiaries.</p>	<p>Title of the Scheme Constitution of the fund</p>
<p>4. The Scheme shall come into force with effect from the date of the notification.</p> <p>5. (a) The Government should make conscious efforts towards building up the Fund corpus to five per cent of the outstanding guarantees within a span of five years from the date of constitution of the Fund.</p> <p>(b) It is open to the Government to increase the contributions to the Fund at its discretion and also based on its assessment of likely invocation of guarantees. The balance in the Fund shall be increased with periodic contributions made annually or at shorter intervals.</p> <p>(c) In order to enable transfer of the total amount of contribution to the Fund, the Government would make suitable Budget provision under the Revenue Expenditure side of the budget under the head "2075- Miscellaneous General Services-797- Transfer to/from Reserve Fund and Deposit Account- 03- Guarantee Redemption Fund".</p> <p>(d) The Government shall not fund its contribution to the Fund out of borrowings from the Bank.</p>	<p>Objective of the Scheme</p>
<p>6. (a) The corpus of the Fund comprises an initial amount demarcated by the Government, annual or other contributions made by the Government thereto as also periodic accretions by way of Guarantee Commission to be collected from the institutions in respect of whose bonds / obligations Government will issue the guarantee, in addition to the income accruing to the Fund.</p> <p>(b) The Fund shall be kept outside the General Revenues of the Government and shall be utilised only in the manner prescribed in this Scheme.</p> <p>7. The Fund shall be administered by Central Accounts Section of the Bank subject to such directions/instructions as the Government may issue from time to time.</p>	<p>Commencement of the Operation of the Scheme Contributions to the Fund</p>
	<p>Relationship of the Fund with General Revenues/Public Account</p>
	<p>Administration of the fund</p>

Investment of the Corpus of the fund	<p>8. The accretions to the Fund together with the income earned on the investment of the Fund shall be invested in Government of India (GoI) Dated Securities, Treasury Bills, Special Securities of the (GoI) and State Government Securities of other States of such maturities as the Bank may determine from time to time. The Bank shall make available the securities for investment either from its investment portfolio or by acquiring the securities from the secondary market, without loading any charge other than that indicated in paragraph 11.</p>
Accounting of Transactions	<p>9. (a) The responsibility for the administration of the Fund will rest with the Government. The Government will decide all matters connected with the investment of the corpus of the Fund, reinvestment/ dis-investment, obligations and application of the Fund, <i>etc.</i></p> <p>(b) The Government will, from time to time, issue instructions to the Bank. The Bank will immediately arrange to make the necessary investment. The Bank would scroll to the Government the debit on account of the investment and other incidental charges like brokerage, commission, <i>etc.</i> in the usual course. However, in order to ensure that the investment transactions of the Fund do not get mixed up with other transactions, these may be indicated distinctly in separate scrolls.</p> <p>(c) On receipt of the scrolls the investment transactions would be accounted for under the head “8235- General and Other Reserve Funds-120- Guarantee Redemption Fund-Investment Account”. However, the incidental charges like brokerage, commission <i>etc.</i>, shall be accounted for as a charge on the Fund.</p> <p>(d) The Bank will arrange to collect interest on these securities and credit the same to the Fund on due date. Further, these would require to be invested as in the case of the contributions by the Government <i>i.e.</i>, in accordance with the investment norms prescribed in para 8 above.</p> <p>(e) On maturity of the securities, the proceeds will be collected and credited to the account of the Government or reinvested in accordance with the pattern outlined in para 8 above on the basis of instructions received from the Government. As in the case of the debit scrolls, the Bank shall use separate scrolls, for the receipts.</p> <p>(f) On receipt of instructions from the Government, the Bank will arrange to sell the securities at the ruling price and credit the amount realized, less incidental charges, to the account of the Government. If these securities are in loss, Bank may in consultation with the Government decide on the securities to be liquidated.</p> <p>(g) The receipts on account of maturity or sale of the securities would be taken into the account of the “Guarantee Redemption Fund- Investment Account”. The incidental charges on sale would be charged to the Fund.</p> <p>(h) The provision for expenditure on account of the Guarantee Redemption will be made in the budget of the Government under the relevant heads. Only the actual amount of guarantee redemption expenditure shall be brought in account under the head “8235- General and Other Reserve fund-120-Guarantee redemption Fund-Investment Account ”.</p> <p>(i) The Bank shall arrange to redeem the securities on maturity. In case of premature disinvestments to meet the liability on account of the claims to be paid, the Bank shall decide on the securities to be liquidated and sell the securities at the ruling price and credit the amount realized, less incidental charges, to the Government account. If these securities are in loss, Bank may in consultation with the Government decide on the securities to be liquidated.</p> <p>(j) The Government will pay the Bank, a commission at the rate determined by the Bank in consultation with the Government. These charges shall also be borne by the Fund as in the case of the charges indicated in paras 9(c) and 9(g). The loss or gain on the sale of securities shall also be taken to the Account of the Fund.</p>

Explanation-

(a) The debit to Government on account of such withdrawal will be accounted under the major head “8235- General and Other Reserve Funds-120-Guarantee Redemption Fund- Investment Account”. On the maturity of the loan the balance outstanding under the head “8235 - General and Other Reserve Funds- 117-Guarantee Redemption Fund” is credited to the head “8680- Miscellaneous Government Account-101-Ledger Balance Adjustment Account”.

(b) The Bank would scroll to the Government the debit on account of investment less the incidental charges in the usual course. However, in order to ensure that the investment transactions of the Fund do not get mixed up with other transactions, these will be indicated distinctly in separate scrolls.

(c) The Bank will arrange to collect interest on the investments and credit the same to the Fund on the due dates.

(d) On the maturity of the securities, the Bank will arrange to redeem the securities and in case of premature disinvestment, to sell the securities at the ruling price and credit the amount realized, less incidental charges to the Guarantee Redemption Fund Investment Account. As in the case of debit scrolls, the Bank shall use separate scrolls for the receipts.

(e) The provision for expenditure on account of the periodic contributions will be made in the Budget of the Government under the relevant head. The extent of expenditure to be financed from the Fund shall be withdrawn from the Fund by the disposal of the investment.

10. (a) The Bank will be guided by the directions of the Government in all matters concerning the investment/ reinvestment/ dis-investment/ reallocation/ withdrawals time to time from the Fund and will act accordingly.

(b) The Bank would arrange to raise a debit to the account of the Government maintained with it as per the schedule of contributions set out in paragraph 5.

(c) The contributions to the Fund shall be invested by the Bank as indicated in paragraph 8. The periodic accretion to the Fund by way of guarantee fee, contributions by the Government and interest income shall also be invested by the Bank in a similar manner.

(d) 50 percent of the outstanding corpus held in the Fund as on March 31 of the preceding financial year, or the amount of guarantees invoked during the year (April- March), whichever is less, should be reckoned for arriving at the maximum eligible limit for withdrawal from the Fund during the year. The Government will replenish the corpus before seeking the next withdrawal.

(e) The Bank will submit periodical statement of balances/ advices regarding the changes therein in consultation with the Government.

11. The Government will pay to Bank a commission at the rate of 1/8 per cent of one per cent of the turnover of the Fund or at the rate to be mutually decided from time to time.

12. The accounts of the Fund and the investments shall be maintained by the Accountant General of the State in the normal course. The concerned Department of the Government will maintain subsidiary accounts in such manner and detail as may be considered by the Government in consultation with the Accountant General.

13. The Government shall issue instructions relating to the provisions of the Scheme as may be considered from time to time to enable smooth functioning of the Scheme. In case of any difficulty in the operation of any provision of the Scheme, the Government may, if satisfied, relax the provisions.

Functions of the
Bank managing
the fund

Service charges
for
administration
of the Fund
Account and
audit

Savings

By order,
DEEPAK KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

